(b) what are the details of the conditions laid down by the World Bank in financing the Project?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) There has been delay in the execution of Upper Indravati Multipurpose Project by Orissa Government.

(b) Under an agreement signed with IBRD/IDA in June 1983 the Upper Indravati Project (hydel portion) will be getting a loan amount of US $ 156.4 million and credit of SDR 156.0 million (US $ 170.0 million) respectively. The irrigation project is not covered under the agreement. The details of the agreement are as under:—

The IBRD loan is repayable over a 20 year period, including 5 years' grace period and carries a 6 monthly variable rate of interest in addition to a commitment charge of 0.75 per cent per annum on the undisbursed balance.

The IDA credits have 50 years repayment period with grace period of 10 years. The credit carries no interest but a service charge of 0.75 per cent per annum is levied on the disbursed balance and a commitment fee of 0.5 per cent per annum on the undisbursed balance.

**टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन**

799. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलिविजन पर दिखाये जाने वाले विज्ञापनों के लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति देने के संबंध में क्या नियम हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विधिवत तैयार की गई वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता दूरदर्शन में मौजूद है और संहिता में निर्धारित मानदंडों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है।

**FCI suggestion on entry of corporate sector in agriculture sector**

800. SHRI SATYA PAL MALIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has made a suggestion to allow corporate sector to enter the agricultural sector; and

(b) if so, what is Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) No concrete proposal has been received in this regard.

**चीनी उद्योग में रुग्णता**

801. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिलों में रुग्णता के क्या कारण हैं तथा क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस रुग्णता को समाप्त करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव)**: (क) चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग होने के नाते उसमें कृषि जलव

सम्बन्धी कारणों समेत बहुत से कारणों से उतार-चढ़ाव आता रहता है। सरकार ने उद्योग में रुग्णता की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार नहीं किए हैं। न्यायमूर्ति वी० भार्गव की अध्यक्षता में सितम्बर, 1970 में स्थापित चीनी उद्योग जांच आयोग से अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया था कि वह बहुत अधिक संख्या में रुग्ण चीनी मिलों के होने के कारणों का अध्ययन करें हाल ही के समय में सरकार ने चीनी उद्योग में रुग्णता की मात्रा या उसके कारणों का कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

**गेहूं, धान और गन्ने के समर्थन मूल्य**

802. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा गेहूं, धान और गन्ने के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रहे है ; और

(ख) मूल्य निर्धारण द्वारा कहां तक गन्ना उत्पादन प्रभावित हुआ है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं और धान के अधिप्राप्ति मूल्य और गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

| मद | विपणन वर्ष | मूल्य (प्रति क्विंटल रु० में) |
|---|---|---|
| गेहूं | 1982–83 | 142.00 |
| | 1983–84 | 151.00 |
| | 1984–85 | 152.00 |
| धान (सामान्य) | 1982–83 | 122.00 |
| | 1983–84 | 132.00 |
| | 1984–85 | 137.00 |
| गन्ना* | 1982–83 | 13.00 |
| | 1983–84 | 13.50 |
| | 1984–85 | 14.00 |

* —8.5 प्रतिशत वसूली से संबंधित है।

(ख) गन्ने का उत्पादन अनेक घटकों पर निर्भर करता है, जिनमें से चीनी कारखानों द्वारा अदा किया गया मूल्य एक घटक है।

**Allotment of flats in pocket B-E, Janakpuri**

803. SHRIMATI MONIKA DAS:
SHRIMATI USHA MALHOTRA:
SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the self-financing flats in Pocket B-E Janakpuri which were likely to be released for allotment by June 1985 have been released;

(b) if not, what are the reasons for the dealy;

(c) the steps taken by the D.D.A. to expedite the completion of this scheme;

(d) the target date if any fixed by D.D.A. for the completion of these flats; and

(e) whether any interest is to be paid on the amounts deposited by the allottees in view of the very long delay and whether such interest will be adjusted against the last instalment to be paid at the time of occupation of the said flats by the allottees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The flats which were earlier expected to be released for allotment by June, 1985, could not be released primarily due to labour shortage with contractor on account of poor organisation of work by him. The work has however, already reached completion stage.

(e) The allottees of these flats will be paid interest for the period beyond 2½ years from the date of allocation @ 7 per cent p.a. and the interest earned by the allottees will be adjusted against the last instalment to